English

Public Transport Forum
New Delhi
20-04-2025

To
The Hon'ble Chief Minister
Government of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, I.P. Estate
New Delhi – 110002

Subject: Request for Evidence-Based Evaluation and Continuation of Women's Free Bus Travel Scheme in Delhi without Discrimination

Respected Chief Minister,

We, the undersigned members of the Public Transport Forum and concerned citizens committed to social and mobility justice, write to express deep concern over your government's recent budget statement alleging "leakage" in the *Free Bus Travel for Women* scheme, currently implemented through the "pink ticket" system.

This scheme was a pioneering step toward enabling women's equal right to the city. It is also a public commitment made by your government during election campaigns, to continue the existing initiative started by the previous administration. It is therefore alarming to see an attempt being made—without public evidence or due process—to cast suspicion on beneficiaries and suggest rollback through restrictive mechanisms such as mandatory smart cards.

Multiple independent studies and surveys, including our report *Riding the Justice Route* (2023), have documented the transformative impact of the scheme. The evidence is clear: this scheme is not a burden, it is a lifeline. Women's ridership increased by 8 percentage points. 23% of women reported increasing their frequency of bus travel. 15% of women who rarely or never used buses earlier now travel regularly. These findings have been echoed in academic and media platforms[1].

In this context, we write to demand the following:

1. Public Disclosure of Evidence

---

1 Please refer to a few of published articles here:
On board Delhi's buses, here's who working-class women availing free transport support this election;
A Free Ticket Can Be a Ticket to Freedom;
Fighting gender inequality through mobility: Assessing Delhi's 'Pink Ticket' scheme;
Delhi govt free bus service boosted women's access to job, education

If “leakage” is the basis for proposed changes, the government must disclose the scale and definition of the alleged leakage, the methodology used to identify such leakage, and the number and categories of women who are being labelled as “wrongful” beneficiaries. In the absence of publicly verified evidence, any reform narrative centred around “leakage” remains speculative and risks being weaponised to undermine hard-won rights and entitlements.

2. Withdraw Discriminatory Remarks Against Refugees

Your government’s oblique reference to Rohingyas and other refugees misusing the scheme is not only baseless, but also dangerous. It legitimises xenophobic narratives and undermines the constitutional idea of governance based on inclusion and pluralism. Concrete concerns, if any, should be addressed through lawful and just means, and not through coded dog whistles.

3. Stop Framing Welfare as a Site of Surveillance

The proposal to make smart cards mandatory risks replacing a functional, accessible, and inclusive system with one that will exclude women without digital access or documentation, criminalise the migrant and the poor, and turn mobility into a site of scrutiny rather than collectivity. The introduction of smart cards is based on a creeping logic of technocratic exclusion disguised as efficiency, and we reject this logic. Technology should only be used to enable, not filter or police, welfare. We demand a public consultation process before the pink ticket system is replaced by smart cards.

4. Govern with Trust, Not Suspicion

This scheme represents not just a subsidy, but a principle: that the city must enable mobility and dignity for all, especially those historically denied it. We urge your government to adopt an approach rooted in: transparency over secrecy, inclusion over exclusion, and rights over gatekeeping.

We also wish to gently emphasise that rather than focusing on problems that may not even exist, the government would do better to channel its energy and resources into strengthening and expanding this crucial scheme. As our report *"Halt for Women"*[2] and multiple media stories have highlighted time and again, a persistent problem remains: **buses often do not stop for women passengers**, especially at night or in less central areas. In this light, there is an urgent need for more buses and more mohalla/DEVI buses across the city. We welcome your government’s recent budgetary commitment to expanding the bus fleet and look forward to seeing this plan implemented swiftly and inclusively.

Today, Delhi needs political leadership that expands, not narrows, women’s rights. Women in Delhi have the right to move safely, freely, and without stigma, and the state has a duty to ensure it. We request you to safeguard the rights-based and

---

2 Halt for Women Bus Users in Delhi: https://www.greenpeace.org/india/en/publication/16078/halt-for-women-bus-users-in-delhi/

universal character of the free bus travel scheme. We hope to receive a formal response and a public statement of intent from your office.

Sincerely,

Members of Public Transport Forum and Concerned Citizens

Signed and Endorsed by

1. Nishant, Coordinator, Public Transport Forum
2.

**A signature campaign has been launched to build wider civil society support for this appeal.*

हिंदी

पब्लिक ट्रांसपोर्ट फोरम
नई दिल्ली
20 अप्रैल 2025

सेवा में,
माननीया मुख्यमंत्री
दिल्ली सरकार
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट
नई दिल्ली – 110002

विषय: महिलाओं के लिए मुफ़्त बस यात्रा योजना का साक्ष्य पर आधारित आँकलन करने और इसे बिना भेदभाव जारी रखने की दरख़्वास्त

माननीया मुख्यमंत्री जी,

हम, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फोरम के सदस्य और दिल्ली के ज़िम्मेदार नागरिक, आपके बजट भाषण में *महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना* को लेकर की गई "लीकेज" (गड़बड़ी) की टिप्पणी पर गंभीर चिंता ज़ाहिर करते हैं।

यह योजना, जो *पिंक टिकट* के ज़रिए चलाई जा रही है, महिलाओं के शहर में बराबरी से आने-जाने के हक़ को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम रही है। योजना को इससे पहले की सरकार ने शुरू किया था और आपकी सरकार ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि इसे जारी रखा जायेगा। ऐसे में अब बिना किसी पुख़्ता जानकारी या सबूत के इस योजना को शक की निगाह से देखना और इसे महिलाओं के एक हिस्से तक सीमित करने की बात करना न सिर्फ़ चिंताजनक है बल्कि महिलाओं के भरोसे को तोड़ने वाला भी है।

हमारे संगठन की रिपोर्ट *"राइडिंग द जस्टिस रूट"* (2023) समेत कई स्वतंत्र रिपोर्टों और मीडिया रिपोर्टों ने इस योजना के बड़े और सकारात्मक असर को साफ़ दिखाया है[3]। इस योजना के बाद महिलाओं की बसों में सवारी 8

---

3 कुछ प्रकाशित लेख यहाँ पढ़े जा सकते हैं:
On board Delhi's buses, here's who working-class women availing free transport support this election;
A Free Ticket Can Be a Ticket to Freedom;

प्रतिशत पॉइंट तक बढ़ी है। 23% महिलाओं ने बताया कि उन्होंने अब पहले से ज़्यादा बार बस से यात्रा करना शुरू किया है। 15% महिलाएं, जो पहले कभी या बहुत कम बस से चलती थीं, अब नियमित चलने लगी हैं।

इस पृष्ठभूमि में, हम आपकी सरकार के सामने कुछ साफ़-साफ़ और ज़रूरी माँगें रख रहे हैं:

1. लीकेज (गड़बड़ी) के सबूत सार्वजनिक किए जाएँ

अगर आपकी सरकार इस योजना में गड़बड़ी या "गलत लोगों को फ़ायदा मिलने" की बात कर रही है, तो कृपया ये स्पष्ट किया जाए: गड़बड़ी का मतलब क्या है और ये कितनी बड़ी है? ये आंकड़े कहाँ से और कैसे जुटाए गए हैं? कितनी महिलाएं इसमें शामिल हैं और किस आधार पर उन्हें फायदा मिलने को गलत ठहराया गया है? जब तक ये जानकारी जनता के सामने नहीं आती, तब तक योजना में बदलाव को लेकर किया जा रहा प्रचार केवल शक पैदा करता है और एक कामयाब और ज़रूरी योजना को बदनाम करने का काम करता है।

2. शरणार्थियों को लेकर दिए गए बयान वापस लिए जाएँ

बजट भाषण में *"रोहिंग्या और दूसरे शरणार्थियों"* का ज़िक्र कर के यह इशारा किया गया कि वो इस योजना का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बयान बेबुनियाद ही नहीं, बल्कि खतरनाक भी है। इससे नफ़रत फैलाने वाली सोच को ताक़त मिलती है और दिल्ली की मिली-जुली, इंसाफ़ पसंद परंपरा को चोट पहुँचती है। अगर कोई वास्तविक दिक्कत है, तो उसका हल कानूनी तरीक़े से होना चाहिए, न कि भाषणों और इशारों के ज़रिए।

3. स्मार्ट कार्ड को ज़बरदस्ती लागू करने का फ़ैसला वापस लिया जाए

गुलाबी टिकट जैसी सीधी और सरल व्यवस्था को हटाकर अगर स्मार्ट कार्ड को ज़रूरी किया जाएगा, तो डिजिटल साधनों या दस्तावेज़ों की कमी से बहुत सी महिलाएं योजना से बाहर हो जाएँगी। ग़रीब, प्रवासी और तकनीक से दूर महिलाएं इससे परेशान होंगी। ये योजना महिलाओं के लिए सुविधा का ज़रिया बनने की बजाय सवाल-जवाब और जांच-पड़ताल का अड्डा बन जाएगी। हम साफ़ कहना चाहते हैं: तकनीक को सहारा बनाइए, दीवार नहीं। हमारी मांग है कि स्मार्ट कार्ड लागू करने से पहले जनता से खुली बातचीत करके राय ली जाये।

4. योजना को शक नहीं, भरोसे की नज़र से देखा जाए

यह योजना सिर्फ़ एक "सब्सिडी" नहीं, बल्कि एक सोच है–कि हर औरत को शहर में इज़्ज़त और आज़ादी से आने-जाने का हक़ मिले। सरकार को चाहिए कि वह जनता पर शक की जगह भरोसा बनाए, अपना हक़ लेने वाले लोगों को आपस में न बाँटे, और अधिकार लेने में और रुकावटें न खड़ी करे।

Fighting gender inequality through mobility: Assessing Delhi's 'Pink Ticket' scheme;
Delhi govt free bus service boosted women's access to job, education

हम यह भी कहना चाहते हैं कि **ऐसी समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय जो शायद हैं ही नहीं**, सरकार को चाहिए कि इस योजना को और मज़बूत करने में ध्यान और संसाधन लगाए। हमारी रिपोर्ट *"हाल्ट फॉर वीमेन"*[4] और कई मीडिया रिपोर्टों ने बार-बार दिखाया है कि **बसें महिलाओं के लिए रुकती ही नहीं हैं**–यह एक लगातार बनी हुई समस्या है। इसके साथ-साथ, हमें दिल्ली में **ज़्यादा बसों और मोहल्ला बसों** की सख़्त ज़रूरत है। हम सरकार द्वारा हाल ही में बसों की संख्या बढ़ाने के लिए की गई **बजट घोषणा** का स्वागत करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसे जल्दी ज़मीन पर उतारा जाएगा।

आज दिल्ली को ऐसा राजनैतिक नेतृत्व चाहिए, जो महिलाओं के हक़ को कम नहीं, बल्कि और पुख्ता करे। हम उम्मीद करते हैं कि आप मुफ्त बस योजना को महिला अधिकार की बुनियाद पर जैसा है, वैसा ही बनाए रखें, और हमारे सवालों के बारे में सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखें।

शुक्रिया,

पब्लिक ट्रांसपोर्ट फोरम सदस्यों और अन्य नागरिकों की ओर से

4 Halt for Women Bus Users in Delhi: https://www.greenpeace.org/india/en/publication/16078/halt-for-women-bus-users-in-delhi/

समर्थन और हस्ताक्षरः

१. निशांत, संयोजक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फोरम

२.

यह पत्र एक जन हस्ताक्षर अभियान का हिस्सा है, जिसमें सिविल सोसाइटी समूह और आम नागरिक इस माँग के समर्थन में जुट रहे हैं।